



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## “भारतीय राजनीति एवं कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव”

डॉ.सुखेन्द्र कुमार गुप्ता  
अतिथि विद्वान-राजनीति विज्ञान  
माता सावित्री बाई फुले  
शा0महाविद्यालय बरियागढ़

डॉ. मुकेश मिश्रा  
अतिथि विद्वान-भूगोल  
माता सावित्री बाई फुले  
शा0महाविद्यालय बरियागढ़

संक्षेपिका :- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही होती है एवं वह अकेला रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसी प्रकार आज वैश्विक वातावरण में कोई भी देश बिना दूसरे देशों से व्यापार या राजनीतिक सम्पर्क किए बिना अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, आज विश्व में प्रतिदिन नए-नए अनुसंधान हो रहे हैं और उनका फायदा दूसरे देशों को तभी मिल सकता है जब वे देश आपस में सम्पर्क में रहेंगे और यही कारण है कि आज वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण संभव हो पाया है क्योंकि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है इसके राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयाम हैं लेकिन मैंने इस शोध पत्र में केवल राजनीतिक एवं कृषि संबंधी आयामों को ही शामिल किया है, यद्यपि वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए कोई भी एक कारण उत्तरदायी नहीं है। इसलिए मैंने इस शोध-पत्र में वैश्वीकरण द्वारा राजनैतिक प्रभावों के अन्तर्गत वैश्वीकरण से देश में सत्ता की शक्तियों में कमी, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी देश की धारणा को अपनाया जाना, राजनीतिक दृष्टि से दे"ा का कमजोर होना आदि को शामिल किया है। दूसरी ओर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव संबंधी कृषि क्षेत्र के संतुलित विकास, किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन आदि को सम्मिलित करते हुए भारत को भविष्य में कृषि के क्षेत्र में जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा इसका अध्ययन किया है। बाजपेयी, अरुणोदय (2002)

कुजी शब्द :- 1.वैश्वीकरण 2.राजनैतिक 3. बहुआयामी 4.अनुसंधान 5. अवधारणा  
6. आयाम 7. कृषि

परिचय:—भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.व्ही. नरसिमहा राव जी ने किया था, और सन् 1991 में वैश्वीकरण से जुड़ने के बाद भारत ने नई आर्थिक प्रक्रिया के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया तथा सन् 1992–93 से रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया और आयात–निर्यात नीति से प्रतिबंध हटाये गए तथा जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया।

वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक परिवर्तन, एकीकृत अर्थव्यवस्था एवं अन्य प्रभावकारी प्रकृतियों के कारण पूरे विश्व का राजनीतिक पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया है और विकसित देशों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम अहस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया तथा संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो चुकी है और इसके फलस्वरूप सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हुई है। किन्तु फिर भी राष्ट्रीय राज्य की महत्ता अभी भी कायम है तथा तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में नागरिकों का जीवन स्तर सुधरा है।

वैश्वीकरण कृषि के क्षेत्र में संतुलित विकास में मदद करेगा और किसानों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हो सकेगा तथा कृषि उत्पादन होगा एवं कृषि में उचित मूल्य प्राप्त होगा। विश्व बैंक ने एक बार कहा था कि विकसित देशों को अनुदान के रूप में 280 रुपये से लेकर 300 अरब डालर विश्व बैंक देता है। पिछली शताब्दी के नब्बे के दशक के बाद से दुनिया को केवल वैश्वीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और देशी राज्यों की राजनीतिक सीमाओं में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार वैश्वीकरण है। शाबा, ओ.पी. (2010)

भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्य सरकारों को नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इस तरह के कार्यों में भारतीय राजनीतिक एवं कृषि को भी शामिल किया गया है जिसका अध्ययन इस शोध–पत्र में किया गया है।

शोध–पत्र की समीक्षा :—समीक्षात्मक दृष्टि से इस शोध–पत्र के माध्यम से भारत में वैश्वीकरण के द्वारा भारतीय राजनीतिक एवं कृषि का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

आंकड़े एवं शोध पद्धति :—इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े के प्रयोग के साथ–साथ कुछ संदर्भित पुस्तकों का सहारा लिया गया है और इसमें वर्णनात्मक, विवर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध पद्धतियों का प्रयोग करते हुये इसे पूर्ण किया गया है।

उद्देश्य :-

1. भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का पता लगाना।
2. भारत में राजनीतिक एवं कृषि के संदर्भ में वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन।
3. वैश्वीकरण के कारण का पता लगाना।
4. वैश्वीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का अध्ययन।
5. वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पूंजीवाद को बढ़ावा संबंधी अध्ययन।
6. वर्तमान समय में वैश्वीकरण का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र :- इस शोध-पत्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण भारत एवं विश्व के उन भागों को सम्मिलित किया गया है जिन पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखा गया है।

स्वीकृति :- मैंने इस शोध-पत्र के विषय का चयन करने से पहले कई विद्वानों से चर्चा की और उस चर्चा के दौरान सभी ने इस विषय पर मुझे शोध पत्र लिखने की स्वीकृति प्रदान की है।

परिणाम :- इस विषय पर शोध करने के उपरांत भारत में वैश्वीकरण से संबंधी राजनैतिक प्रभाव का यह परिणाम निकलकर आता है कि वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में से एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है और भारत की समप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें राजनीतिक एवं कृषि संबंधी पहलुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा और सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण भारत की क्षमता अर्थात् सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है और पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी हो गई है और इसकी जगह अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। वही दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण संतुलित विकास में मदद करेगा, किसानों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आदि पर प्रभाव डालेगा क्योंकि भारत वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। अतः इसका प्रभाव भारत की कृषि के हर क्षेत्र पर पढ़ रहा है। मिश्रा के.के. शुक्ला (2010)

## तालिका -1

## परियोजनाओं के रूप में भू-मण्डलीकरण/वैश्वीकरण

क्रं.	भू-मण्डलीकरण/वैश्वीकरण परियोजनाएँ	अभिकर्ता
1.	विकासात्मक विश्ववाद	विश्व बैंक सयुक्त शब्द एजेंसियां जैसे- यू.एन.डी.पी. आदि।
2.	संचार माध्यम विश्ववाद	मीडिया, सी.एन.एन.।
3.	श्रम विश्ववाद	टाई एल.ओ. मजदूर संघ अन्तर्राष्ट्रीयवाद।
4.	इस्लामिक विश्ववाद	उल्लमा राजनीति।
5.	संघबद्ध विश्ववाद	अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं पराराष्ट्रीय उद्यम।
6.	प्रति विश्ववाद	स्थानीयवाद, नव संरक्षणवाद एवं नियोजन।
7.	नारी अधिकारवादी विश्ववाद	नैरोबी, बीजिंग एवं बैरो अधिवेशन।

स्रोत :- पीटर्स 2001

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि वैश्वीकरण एवं बहुमुखी एक बहुआयामी दृश्यधारना है जिसका एक समग्र श्रृंखला पर अपना संभावित प्रभाव होता है।

## तालिका -2

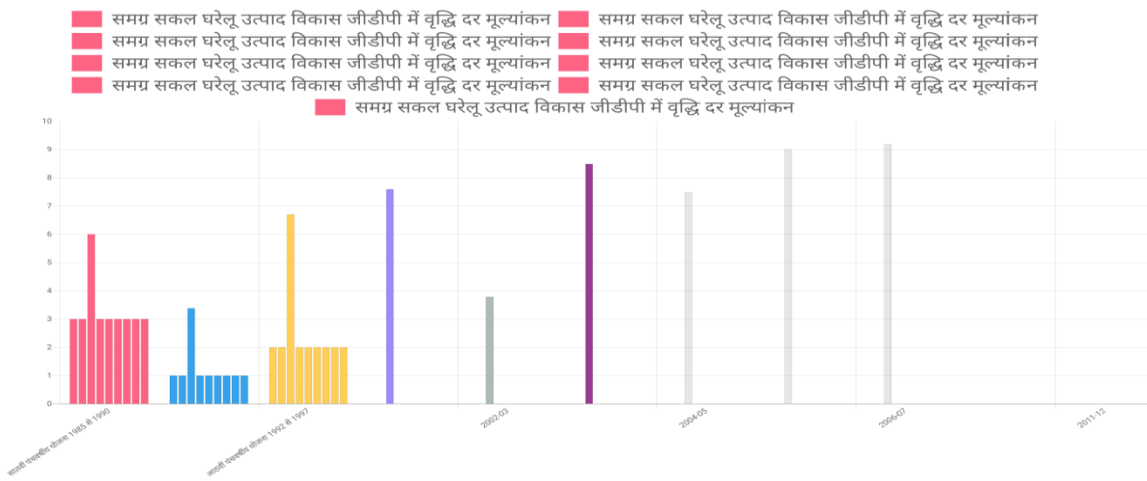
कृषि एवं सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्रं.	पंचवर्षीय योजना	समग्र सकल घरेलू उत्पाद विकास जी.डी.पी. में वृद्धि दर (मूल्यांकन)	समग्र सकल घरेलू उत्पाद विकास जी.डी.पी. में वृद्धि की दर (कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में)
1.	7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)	6.0	3.2
2.	वार्षिक योजना (1990-1992)	3.4	1.3
3.	8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)	6.7	4.7
4.	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)	7.6	2.3
5.	2002-03	3.8	7.2
6.	2003-04	8.5	10.0
7.	2004-05	7.5	0.00
8.	2005-06	9.0	6.00
9.	2006-07	9.2	2.7
10.	2010-11	NA	7.9
11.	2011-12	NA	3.6

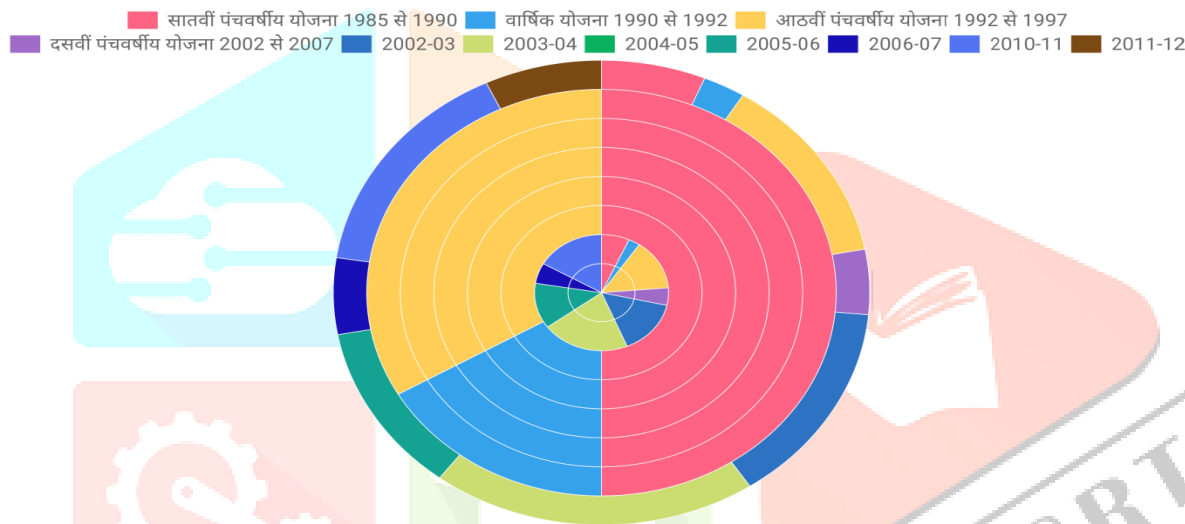
स्रोत :- आर्थिक सवेक्षण, भारत सरकार वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2012-13 (NA= उपलब्ध नहीं है।)

उपयुक्त तालिका में भारत को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में कृषि एवं सकल घरेलू उत्पाद में वास्तव में वार्षिक औसत वृद्धि दर क्या रही है इसके बारे में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है।

चित्र:-2.1 समग्र सकल घरेलू उत्पाद विकास जी.डी.पी. में वृद्धि दर (मूल्यांकन)



चित्र:-2.2 समग्र सकल घरेलू उत्पाद विकास जी.डी.पी. मं वृद्धि की दर  
(कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में)



विचार विमर्श :-इस शोध विशय पर गहन विचार विमर्श किया गया है जैसे क्या भारतीय राजनीतिक एवं कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ रहा है या नही और कई विशय विशेषओं से विचार-विमर्श उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि यह विशय शोध हेतु उचित है इसलिए मैंने यह शोध पत्र बनाया है।

सिफारिश :-मेरे संपर्क में कई ऐसे विद्वान है जिनकी समय-समय पर में सलाह लेता हूँ और प्रो. आर.पी. मिश्रा (डीन) डॉ. हरिसिंह गौर वि. वि. सागर में पदस्थ है उनसे मैंने अपने इस शोध शीर्षक से संबंधित चर्चा की जिस दौरान उन्होंने मुझे इस विशय पर शोध पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया और मैंने शोध पत्र लिखा एवं इसे लिखने से मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि वर्तमान समय में यह शोध शीर्षक प्रासंगिक है।

निष्कर्ष :-अंत में निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते है कि आज वैश्वीकरण शब्द विश्वव्यापी विकास की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दुनिया के हर कोने में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने या बेचने के कारण ही यह अब संभव है तथा संचार के साधन, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और परिवहन इसी की सुविधाओं का ही अंश है। इस

प्रकार वैश्वीकरण की अवधारणा का विकास भू-मण्डलीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है तथा शब्द अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था एकीकरण को एकीकृत करना वैश्वीकरण का मतलब है, जैसे माल और सेवाओं, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विश्व बाजार के साथ घरेलू बाजार श्रम आदि एवं ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूँजी प्रवाह और वित्त प्रवाह की ही एक प्रक्रिया है। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक एवं कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण एक ज्वलंत प्रक्रिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- बाजपेयी, अरुणोदय (2002) : पूर्वोद्धत, पृष्ठ-18
- मिश्रा के.के शुक्ला (2010) : "अंतराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत", अनामिका पब्लिसर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ-37
- बाजपेयी अरुणोदय (2012): "समकालीन विश्व एवं भारत", डॉलिंग किंडरस्ले (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली, पृष्ठ-8
- शाबा, ओ.पी. (2010): "राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा", मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, पृष्ठ-36
- Burk,M.C. and Ezekiel,M.(1970): Agricultural Development in Economic Growth,Cornell University press,pp,51,61.
- Brown,D.D. (1971): Agricultural Development in India's Districts ,Harvard University Press,pp,78,91.
- Basu,S.R. (1979): Development of water Resources of North-Eastern Region of India,pp,71,72.
- Byress,T.J. (1972): The Dialectics of India's Green Revolution,south Asian Review,pp,114,116.
- Chouhan,T.S. (1987): Agricultural Geography,Jaipur,pp,47.
- Chadha,R.S. (1967): Growth and Stagnation in Agriculture Agricultural Situation in India,pp,78,79.
- Chatterjee,Nondini (1986): Methods for crop combination in regions of west Bengal Indian Journal of Land scap System,pp,40,41
- Dharandhar,K.P. (1974): Soil Structure of Madhya Pradesh,The Indian Geographical Review,pp,30,31.
- Dubey,R.S. (1987): Agricultural Geography,Issues And Applications,Gian publishing,New Delhi,pp,34,37.
- Government of India (1946): The Food statistics of India,Department of Food,New Delhi,pp,40,70.
- Hayami-yujiro and Vernon Ruttan (1977): Agricultural Development,John,Hopkins,Press,pp,29,30.
- Hunter,G.ed. (1978): Agricultural development and Rural Poor,Concept publication company,New Delhi,pp,19,20.
- Harvey,D.W. (1966): Theoretical concepts and the Analysis of Agricultural land use patterns in Geography,pp,10,11.
- Iserma,P.J. and Singer,H.O. (1977): Food Aid Its potential Disincentives to Agriculture Development Digest,pp,108,118.
- Johi,Y.G. (1968): The patterns of Agriculture in the Narmada River Basin,India,New Delhi,pp,40,41.